

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी गंभीर

सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी निःसंदेह बहुत गंभीर है कि संविधान को लागू हुए पचहतर वर्ष हो गए, अब तो कम से कम पुलिस को अधिकारिकी की आजादी का अर्थ समझना चाहिए। हालांकि यह टिप्पणी कोई पहली बार नहीं आई है। इससे पहले भी कई मौकों पर वाक् और अधिकारिकी की स्वतंत्रता पर बहसें हो चुकी हैं, अदालतें पुलिस को नसीहत दे चुकी हैं, मगर शायद उस पर संजीदी से अमल की जरूरत नहीं समझी गई। इसी का नतीजा है कि अब भी जब तब ऐसे मामले अदालतों में पूछंच जाते हैं, जिनसे किसी की भावना के आहत होने का आरोप लगता है, जबकि वास्तव में उनमें ऐसा कुछ नहीं होता।

चाहे वह फिल्मों के दृश्यों-संवादों, किसी राजनेता के बयानों या साहित्य के किसी अंश को लेकर भावनाएं आहत करने या भड़काने के आरोप लगते रहे हों या किसी ऐतिहासिक-मिथकीय प्रसंग को लेकर की गई टिप्पणी पर। कई बार तो कुछ बातों को लेकर आंदोलन तक उभारने की कोशिशें देखी गई हैं। तजा सामाला कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी की एक कविता को लेकर उठा, जब उन्होंने युजरात के एक विवाह समारोह में उसे सुनाया और फिर सोशल मीडिया पर उसका अंश डाल दिया। उन पर आरोप लगा कि कविता में लोगों में हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया है। वहाँ की पुलिस ने इस पर मुकदमा भी दर्ज किया।

साहित्य और कलाओं में अधिकारिक विचार कई बार प्रतीकों और बिंदों में छिपे होते हैं, इसलिए उनके सही अर्थ खोलने में दिक्षित आ सकती है। प्रतापगढ़ी के मामले में युजरात पुलिस को भी इसी के चलते धोखा हुआ होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट भी किया कि अनुवाद में गलती की वजह से यह भ्रम हुआ होगा। मगर आजकल जिस तरह चुनिंदा तरीके से किसी के बयानों से भावनाओं के आहत होने के आरोप कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ भी कहते बोलते देखे जाने लगे हैं। धर्म संसदों और कई सर्वजनिक सभाओं में सतों और राजनेताओं के आपत्तिजनक बयान देखे-सुने गए, मगर उनमें पुलिस का रवैया पक्षपातृपूर्ण ही देखा गया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस को कुछ तो संवेदनशीलता दिखानी होगी।

हालांकि यह छिपी बात नहीं है कि पुलिस स्वायत्त तरीके से काम नहीं करती। अनेक कार्रवाइयां उसे सत्ता पक्ष के दबाव में करनी पड़ती हैं। इसलिए विपक्षी दलों के मामले में अगर अधिकारिकी की आजादी के कानून को हासिले पर धकेल दिया या नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो हैरानी की बात नहीं। यह कम बड़ी विडंबना नहीं कि साहित्य और कलाओं में अधिकारिक विचारों की व्याख्या भी अदालतों को करनी पड़ रही है। सताएं सदा से अपनी आलोचना से तब्दि हो जाती रही हैं, पर आखिर अधिकारिकी की स्वतंत्रता की रक्षा कीरण करेगा। पहला कर्तव्य तो पुलिस का ही बनता है कि वह उसकी सही-सही व्याख्या करे और फिर कानूनी कार्रवाई के बारे में सोचे। पर राजनीतिक उदारता के बगैर यह संभव नहीं जान पड़ता।

नईदुत्तिया

महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने का वक्त

(8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष)

इमेश सर्पण धमोरा

भारत वह देश है जहाँ महिलाओं की सुरक्षा और इन्जित का खास ख्याल रखा जाता है। अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो यहाँ की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रही हैं। अब तो भारत की संसद ने भी महिलाओं के लिए लोकसभा विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पास कर दिया है। इससे आने वाले समय में भारत की राजनीति में महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होनी तय है। देश में महिलाओं को अब सेना में भी महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाने लगा है। यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा क्रम है।

यहाँ महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार है। महिलायें देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा विकास में भी बाहर कर की भागीदार हैं। आज के युग में महिला पुरुषों के साथ ही नहीं बल्कि उनसे दो कदम आगे निकल चुकी हैं। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को भी पुरुषों के समान जीवन जीने का हक है। भारत में नारी को देवी के रूप में देखा गया है।

कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ महिलाओं को समाज में भी देखी जाती हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्तीत अधिकारिकी की कांस्कल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार इसके उलट भी देखी जाती हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के